गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पटना जंक्शन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षा गृह की साज-सफाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एस.पी.जी. की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए उनके पटना जंक्शन पर 30.6.1996 की शाम को दौरा करने के संबंध में की गयी थी। यह एस.पी.जी. अधिकारी द्वारा कहा गया था। एस.पी.जी. के अधिकारी को, जो एस.पी.जी. अधिनियम के अन्तर्गत अपनी ड्यूटी कर रहा था, माननीय संसद सदस्य की पहचान नहीं थी। तथापि एस.पी.जी. के सभी अधिकारियों को उपयुक्त रूप से ब्रीफ कर दिया गया है।

वसन्त कुन्ज में व्याप्त असुरक्षा

832. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) 'टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार के अनुपूरक 'डेली टाइम्स' में "देयर इज़ ए सेन्स ऑफ इनसिक्योरिटी इन वसन्त कुन्ज" शीर्षक से 14.10.97 को छपी खबर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच किसी तीसरी एजेंसी को सौंपने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान, वसंत कुंज के सैक्टर "ए" पाकेट "बी" और "सी" में लूटपाट के चार मामले सूचित हुए जिनमें से तीन मामले हल कर लिए गए और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस कार्मिक तैनात किए हैं तथा क्षेत्र में घूमने-फिरने वाले अज्ञात व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जाँच कार्य किसी अन्य तीसरी एजेंसी को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Border dispute between Maharashtra and Karnataka

833. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to examine various aspects concerning the issue to settle the Maharashtra-Karnataka Border dispute;

(b) whether Government consider and propose to hold and opinion poll in the Border areas to know the wishes of the people;

(c) if so, by when;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) by when the border dispute is likely to be settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) The boundary dispute between Maharashtra and Karnataka has been pending ever since the reorganisation of States in 1965. The Government of India had, in 1966, appointed the Mahajan Commission to look into this issue. While the Government of Karnataka accepted the recommendations made by the Commission in toto, the Government to Maharashtra rejected the same. The Government of India had also convened meetings with the concerned State Chief Ministers to resolve the issue but the differences are still persisting.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e) The Government of India is of the view that the dispute is to be resolved primarily by the State Governments concerned through discussions and mutual accommodation, and it would be too glad to render any assistance to them in this regard.

लापता महिलायें

834. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विवाहित महिलाओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या विवाहित महिलाओं को उनके ससुराल वालों द्वारा यातनायें दिये जाने की घटनाओं के समाचार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान और अब तक लापता हुई महिलाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरका. ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) चूंकि पुलिस और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अत: अपराधों का पंजीकरण करना जांच करना, ता लगाना और रोकथाम करना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। संदेहास्पद स्थितियों में लापता हुई विवाहित महिलाओं संबंधी आंकड़े एक पृथक शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1996 के दौरान घटित "अपहरण एवं व्यपहरण और पति एवं उसके संबंधियों द्वारा निर्दयता करने" की घटनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना विवरण में संलग्न है। (**नीचे देखिए**)

केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हुई अत्याचार की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करती है। यह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में आवश्यक रूप से किये जाने वाले निवारात्मक दण्डात्मक और पुनर्वासीस उपायों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई योजनायें चलायी हैं।

विवरण

वर्ष 1996 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों की घटनायें (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्रम सं.	राज्य	अपहरण एवं व्यपहरण	पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	अनुक्तियां (महीना जिस तक के आंकड़े दिए गए हैं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	53	2386	नवम्बर
2.	अरूणचल प्रदेश	13	0	सितम्बर
3.	असम	600	236	नवम्बर
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	--
5.	गोवा	10	12	
6.	गुजरात	599	1910	
7.	हरियाणा	373	485	
8.	हिमाचल प्रदेश	131	211	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	127	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	332	1383	
11.	केरल	167	881	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1561	2057	
13.	महाराष्ट्र	940	8589	
14.	मणिपुर	53	2	
15.	मेघालय	0	0	फरवरी
16.	मिजोरम	3	0	
17.	नागालैंड	0	0	
18.	उड़ीसा	316	396	अक्तूबर
19.	पंजाब	184	194	
20.	राजस्थान	2488	3900	
21.	सिक्किम	8	1	
22.	तमिलनाडु	568	366	
23.	त्रिपुरा	45	69	
24.	उत्तर प्रदेश	2562	3649	
25.	पश्चिम बंगाल	765	3181	
	कुल राज्य	12387	29910	
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और नि.द्वीप समूह	4	5	
27.	चण्डीगढ़	26	13	
28.	दा. और न. हवेली	3	6	
29.	दमण और द्वीव	उ.न.	उ.न.	
30.	दिल्ली	944	150	
31.	लक्षद्वीप	0	0	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	5	2	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	982	176	
	कुल (अखिल भारत)	13369	30086	

Jain Commission Report

835.SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether complaints have been received by Government that certain documents of sensible nature are not being made available to the Jain Commission;

(b) whether it is also a fact that a demand has been made that the Commission's interim report be made public; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir, but the Government is committed to extend full co-operation to the Jain Commission of Inquiry and is extending the same.